

१०२

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—पार्ट 1
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 1993/माघ 15, 1914

No. 27] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1993/MAGHA 15, 1914

इस भाग में भिन्न पुस्तक संलग्न वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य भंडालय

सार्वजनिक सूचना सं. 101/(पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1993

फाइल सं. 6/14/92-ई पी सी:—नियात आयात-नियात, 1992-97 के पैराग्राफ
16 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महानिवेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया
पुस्तक, 1992-97 में निम्नलिखित संशोधित करते हैं:—

1. अध्याय-15 के पैराग्राफ 233 में अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

“तथापि, नियात संबंधीत पूँजीगत माल स्कीम के अन्तर्गत संबंधित पूँजीगत माल के
अनुरक्षण के लिए अपेक्षित मानक अतिरिक्त पुजों का आयात पूँजीगत माल के बीच

भारत सरकार मूल्य के 10% तक किया जाएगा बशर्ते कि पूँजीगत माल के साथ अतिरिक्त पुराने का भी आयात किया जाए। ऐसे अतिरिक्त पुराने का आयात नीति पुस्तक के पैरमाणक 38 में नियोगित नियंत्रित वायित्व के व्यवधान किया जाएगा।

2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

सी. के. मोदी, महानिदेशक, विक्रेता व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 101(PN) | 92—97

New Delhi, the 4th February, 1993

File No. 6|14|92-EPC(pt.)—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992—97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures, 1992-97 :—

1. In Chapter XV, paragraph No. 233, the following shall be added at the end :—

"However, under the Export Promotion Capital Goods Scheme, standard spare parts required for the maintenance of the concerned capital goods may be imported upto 10 per cent of the cif-value of the capital goods provided the spare parts are imported alongwith the capital goods. Such import of spare parts shall be subject to the export obligation as prescribed in paragraph 38 of the Policy Book".

2. This issues in public interest.

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade